तथापि, पहली बार किए गए आवंटनों के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते और उच्च श्रेणी के आवासों के आंकड़े अलग से रखे जाते हैं।

(ग) आवंटन की प्रणाली को कारगर बनाने के लिए मकानों के स्टाक की उपलब्धता को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। आवेदनों की प्रतीक्षा सूची की स्थिति को भी कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

शिकायतों पर ध्यान देने तथा आवास सम्बन्धी पूछताछ का उत्तर देने के लिए एक जन कल्याण अधिकारी को नामित किया गया है।

(घ) नीतिगत मामले के अनुसार स्वायत्त संगठन के कर्मचारी सामान्य पूल के आवास आवंटन के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, इस प्रकार के कुछ संगठनों के लिए विशेष कारणों को लेकर इस नीति में छूट दी गई है।

(ङ) भारत की संचित निधि से वेतन लेने वाले अधिकारी साधारण पूल के आवास के आवंटन के लिए पात्र हैं। साधारण पूल के आवासों में कमी को देखते हुए इसमें किसी प्रकार की ढील/छूट आमतौर पर नहीं दी जाती है।

देश में द्रुतगामी परिवहन प्रणाली

2449. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में द्रुतगामी परिवहन प्रणाली के अधीन रेल गाड़ियों की यातायात समस्याओं को हल करने की दिशा में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान शहरी परिवहन प्रणाली के अधीन चल रही रेल गाड़ियों के नवीकरण ; अनुरक्षण और प्रचालन के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1990 के दौरान कुल कितनी राशि खर्च की गई थी और इससे किन-किन शहरों को लाभ हुआ है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न सेवाओं के लिए कोई पृथक बजटीय प्रावधान नहीं किया जाता है। व्यय संयुक्त रूप से किया जाता है तथा बाद में विभिन्न सेवाओं में नयोजित किया जाता है।

(ग) बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के महानगरीय क्षेत्रों में रेल-बेसड कम्प्यूटर सेवाओं पर 1989–90 के लिए लगभग 514 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था।

दिल्ली में आवास आदि की समस्या

2450. श्री रणजीत सिंह :
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान आवास समस्या और महानगर की अन्य समस्याओं को हल करने हेतु दिल्ली के विस्तार के लिए कोई प्राधिकरण स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, ऐसा प्राधिकरण कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ; और

(ख) दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों की ऐसी समस्याओं का ब्यौरा क्या है जिनको उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा उठाए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) बड़े राजधानी क्षेत्र के सन्दर्भ में दिल्ली के आर्थिक क्रिया-

कलापों, रोजगार और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की समस्याओं की जांच करने हेतु सरकार पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन कर चुकी है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नगरों का विकास

2451. चौधरी हरि सिंह :
श्री शांति त्यागी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों के लिए 1990-91 के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई है और ऐसे जिलों में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अधीन आने वाले जिले की निधि आवंटन में कोई प्राथमिकता दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे जिले का नाम क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान निधियों का जिलावार नियतन नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) निधियों के नियतन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतगत किसी भी जिले को प्राथमिकता नहीं दी गई थी । तथापि, क्षेत्र में निम्नलिखित चुनींदा कस्बों को विकास में प्राथमिकता दी गई है :—

उत्तर प्रदेश में—मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर और खुर्जा :

हरियाणा में—पानीपत, रोहतक, रिवाड़ी, झाड़सा और पलवल ; और राजस्थान में—अलवर तथा भिवाड़ी ।

Rereservation of Plots in the big cities of the Country

2452. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SOM PAL:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that dereservation of plots in. big cities in the country is actively encouraged by vested interests, particularly builders lobby thereby harming the urban development if so, what are the measures contemplated by Government to prevent such dereservation; and

(b) whether it is also a fact that such dereservation of plots is leading to cutting down of the infrastructure lay outs of schools, parks, hospitals and roads etc. and helps increase crowding and congestion?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KATJL): (a) and (b) Dereservation of plots is within the ambit of the local bodies and state Government concerned and the Government of India does not have any role to play in the matter.

Unauthorised Construction in Ashok Vihar

2453. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI; Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints about the unauthorised construction in the DDA flats in Pocket 'A' phase-III, Ashok Vihar, Delhi;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government have taken|proposed to take in the matter?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) and *(b) The* DDA has reported that complaints have been received regarding unauthorised construction made in flats No; 19-B and